

प्रेषक,

भास्करानन्द,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
अल्मोड़ा।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक | 6 जनवरी, 2015

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में उप क्षेत्रीय विज्ञान (साईंस पार्क) की स्थापना हेतु कुल 1.254 हौं भूमि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-375/बारह-02/2009-10 दि0-17.10.2013 तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0-6755/राजस्व/2013 दि0-22.11.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद अल्मोड़ा में राजस्व विभाग के नाम दर्ज ग्राम पोथ प्री स्टेट की ज0वि0 के ख0खा0 सं0-3 में अंकित भूमि में से 1.254 हौं भूमि जो श्रेणी 1क संकमणीय भूमिधरी है, को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15.02.2002 के प्राविधानों के अधीन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- (1) भूमि हस्तान्तरण के पूर्व जिलाधिकारी, अल्मोड़ा इस बात की पुष्टि कर लेंगे कि प्रश्नगत भूमि निजी भूमि के अंतर्गत नहीं है।
- (2) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- (3) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- (4) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (5) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- (6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- (7) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

27

(8) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(9) प्रश्नगत जेड०ए० भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस०एल०पी०)/(सी) संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

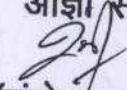
भवदीय,

↙  
(भास्करानन्द)  
सचिव।

पू०प०संख्या- 164 / समदिनांकित / 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।  
2— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।  
3— आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।  
4— निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।  
5— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(संतोष बडोनी)  
अनुसचिव।